2011:CGHC:8686

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5843/2009

याचिकाकर्ता कवल सिंह गौतम

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

और

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5857/2009

याचिकाकर्ता डुमेश्वर कुमार लिल्हरे

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-
मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5843/2009

याचिकाकर्ता कवल सिंह गौतम

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

और

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5857/2009

याचिकाकर्ता डुमेश्वर कुमार लिल्हरे

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन याचिकाएं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति-

श्री अनूप मजूमदार, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता।
श्री वी.वी.एस. मूर्ति, राज्य के लिए उप महाधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 09.02.2011 को पारित**)**

1. इन दो याचिकाओं में, अवधारण और न्यायनिर्णयन के लिए उत्पन्न प्रश्न समान हैं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद "2005 का अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट) के तहत याचिकाकर्ताओं के सूचना के अधिकार से संबंधित हैं।
2. इन दोनों याचिकाओं की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि काफी समान है। इन याचिकाओं में की गई प्रार्थना यह है कि मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश, जो अपीलीय प्राधिकारी और लोक सूचना अधिकारी के आदेश की पुष्टि करता है, को अपास्त किया जाए और

प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता की उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। प्रत्येक याचिका के व्यक्तिगत तथ्य, जो इस न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी को जन्म देते हैं, नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

रिट याचिका (सी) संख्या 5843/09 में याचिकाकर्ता- कवल सिंह गौतम, जो शासकीय हाई स्कूल सुकुलदैहान, राजनांदगांव में लेखापाल के पद पर पदस्थ हैं, वर्ष 2007 में कोषालय, लेखा एवं पेंशन विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उपस्थित हुए। उन्होंने परीक्षा में कुल 255 अंक प्राप्त किए। यद्यपि, दो विषयों में, उन्होंने 64 से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन अन्य 3 विषयों में, उन्हें उनकी अपेक्षा से कम अंक प्रदान किए गए। दिनांक 12.6.2008 को, उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत आवश्यक शुल्क का भुगतान करके तीन विषयों की आकलित/जांची गई उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए नामित लोक सूचना अधिकारी को एक आवेदन (अनुलग्नक पी-3) दिया। उनके आवेदन के उत्तर में, लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 25.6.2008 (अनुलग्नक पी-4) के माध्यम से सूचित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी उन्हें प्रदान नहीं की जा सकती है। यह कहा गया कि याचिकाकर्ता की उत्तर-पुस्तिका का प्रदाय एक ऐसी जानकारी है जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटन का किसी भी लोक क्रियाकलाप या हित से कोई संबंध नहीं है। यह भी कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग ने उत्तर-पुस्तिकाओं के प्रदाय को निषिद्ध किया है और यह व्यापक लोक हित में नहीं है, और इसलिए, 2005 के अधिनियम की धारा 8(1)(ङ) के तहत निहित प्रावधान को देखते हुए, ऐसी जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है। 2005 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने पर, अपीलीय प्राधिकारी ने **श्री विवेक कुमार बनाम लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली** के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश का संदर्भ देते हुए अपील को खारिज कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि परीक्षा का संचालन गोपनीय कार्यवाही है और लोक हित उत्तर-पुस्तिका के प्रदाय की अनुमति नहीं देता है, जैसा कि 2005 के अधिनियम की धारा 8(1)(घ) में प्रावधान निहित है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अंततः छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष अपील की, जिसे मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक 28.2.2009 के आदेश के माध्यम से खारिज

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कर दिया गया। आयोग ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और लोक सूचना अधिकारी के आदेश में निहित 2005 के अधिनियम की धारा 8(1)(ङ) और धारा 8(1)(ञ) के प्रावधानों के संदर्भ में अस्वीकृति के कारणों की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त, यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि परीक्षा की पवित्रता को देखते हुए और यह कि उत्तर-पुस्तिका की प्रति प्रदान करने की स्थिति में अराजकता हो सकती है, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायोचित और उचित पाया गया। तथापि, अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को सुनने के बाद अपील खारिज करने के अपने आदेश को संशोधित करने का प्रयास किया और उत्तर-पुस्तिकाओं के निरीक्षण की अनुमति देते हुए अपने आदेश को संशोधित किया। इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने उत्तर-पुस्तिकाओं का निरीक्षण किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने पाया कि उनकी उत्तर-पुस्तिका की ठीक से जांच नहीं की गई थी और परीक्षकों के उपेक्षापूर्ण रवैये को देखते हुए, याचिकाकर्ता, जो परीक्षक द्वारा किए गए मूल्यांकन को चुनौती देने के इच्छुक हैं, ने अब इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है ताकि प्रत्यर्थीगण प्राधिकारी को सूचना के अधिकार के तहत उनके आवेदन में उल्लिखित विषयों के संबंध में याचिकाकर्ता की उत्तर-पुस्तिका की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने का निर्देश जारी किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सी) संख्या 5857/09 में याचिकाकर्ता डुमेश्वर कुमार, जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेदीकला, राजनांदगांव के कार्यालय में लेखापाल के रूप में पदस्थ हैं, भी वर्ष 2007 में कोषालय, लेखा एवं पेंशन विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उपस्थित हुए थे। उन्होंने कुल 243 अंक प्राप्त किए और अन्य तीन विषयों में उन्हें दिए गए अंकों से संतुष्ट न होने पर, लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत करके आकलित/जांची गई उत्तर-पुस्तिकाओं की आपूर्ति के लिए आवेदन किया। उनका आवेदन भी दिनांक 25.6.2008 के आदेश द्वारा इसी तरह के तर्क पर खारिज कर दिया गया, जिसमें 2005 के अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) और 8(1)(ङ) में निहित प्रावधानों का सहारा लिया गया, जिसके बाद इस याचिकाकर्ता ने अपील की, जिसे भी समान आधारों पर खारिज कर दिया गया। अंततः, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष की गई अपील पर, दिनांक 28.2.2009 के आदेश द्वारा, अपीलीय प्राधिकारी ने अन्य याचिकाकर्ता के मामले की तरह समान आधारों पर

अपील को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में उत्तर-पुस्तिकाओं के निरीक्षण की अनुमति देकर अपने आदेश को संशोधित किया। चूंकि इस मामले में याचिकाकर्ता भी न्यायालय में उपचार का सहारा लेकर अपने मामले में परीक्षक द्वारा किए गए मूल्यांकन को चुनौती देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भी अपनी स्वयं की जांची गई/आकलित उत्तर-पुस्तिकाओं की आपूर्ति के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है।

3. दोनों मामलों में, जिन कारणों को निर्दिष्ट किया गया है और 2005 के अधिनियम के जिन प्रावधानों का सहारा लेकर आवेदन खारिज किया गया है और जिन आधारों पर प्रथम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील खारिज की गई है, वे भी समान हैं।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रबलता से तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को 2005 के अधिनियम की धारा 3 के तहत सूचना का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। याचिकाकर्ता उनके द्वारा मांगी गई जानकारी के हकदार हैं और लोक सूचना अधिकारी विधि के तहत उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करने और 2005 के अधिनियम की धारा 3 में निहित विधिक आदेश को देखते हुए याचिकाकर्ताओं की आकलित/जांची गई उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने के लिए बाध्य थे। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की आगे का तर्क यह है कि जहां तक 2005 के अधिनियम की धारा 8(1)(ङ) और 8(1)(ञ) के तहत दी गई शिथिलता की प्रयोज्यता का संबंध है, वर्तमान मामला किसी भी वैश्वासिक संबंध के अस्तित्व का मामला बिल्कुल नहीं है जो सूचना के प्रकटन में प्रदान करे, क्योंकि दोनों याचिकाकर्ताओं ने किसी तीसरे पक्ष से संबंधित किसी भी जानकारी के प्रकटन की मांग नहीं की है, बल्कि उन्होंने अपनी स्वयं की आकलित/जांची गई उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति की मांग की है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की दूसरी दलील यह है कि 2005 के अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के तहत बनाई गई छूट को भी लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की ओर से विधि की भ्रामक धारणा के तहत गलत तरीके से लागू किया गया है, क्योंकि इसे व्यक्तिगत जानकारी नहीं कहा जा सकता, जिसके प्रकटन का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से कोई संबंध नहीं है, जैसा कि प्राधिकारियों द्वारा कहा गया है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 2005 के अधिनियम की धारा 8(1) के खंड (ङ) और (ञ) द्वारा कवर किए गए मामलों के संबंध में भी, जब व्यापक लोक हित ऐसी जानकारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के प्रकटन की मांग करता है, तो जानकारी के प्रकटन के खिलाफ कोई पूर्ण रोक नहीं है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील है कि संबंधित विषयों की परीक्षा में याचिकाकर्ता के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय परीक्षकों/जांचकर्ताओं की अवैधता और मनमानापन, लापरवाही, भ्रांति और लापरवाह रवैये को समुचित कार्यवाही में प्रदर्शित करने के लिए याचिकाकर्ताओं को उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं की आपूर्ति आवश्यक है। अपनी दलील और याचिका में की गई प्रार्थना के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रीतम रूज बनाम कलकत्ता विश्वविद्यालय और अन्य**[1] के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है, जिसकी पुष्टि उस न्यायालय की खंडपीठ ने अपील में की थी, जो **ए.आई.आर. 2009 कलकत्ता 97** में प्रतिवेदित है। **सेक्रेटरी जनरल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल**[2], **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम मोहम्मद शाहजहां**[3] **और सेंटर ऑफ अर्थ साइंस स्टडीज, तिरुवनंतपुरम बनाम डॉ. (श्रीमती) एनसन सेबेस्टियन एवं अन्य**[4] के मामलों के निर्णयों का भी अवलंब लिया है।

5. दूसरी ओर, दोनों मामलों में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संबंधित विषयों में अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ताओं का दावा विधि में असमर्थनीय है, क्योंकि 2005 के अधिनियम की धारा 8(1)(ङ) और 8(1)(ञ) के तहत दी गई छूट स्पष्ट रूप से आकर्षित होती हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन को सही ढंग से खारिज किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि भले ही अपनी संबंधित उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति के लिए दो रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिसे द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी ने बरकरार रखा है, वास्तव में प्रत्येक मामले में याचिकाकर्ताओं को उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं के निरीक्षण की अनुमति दी गई थी। उनकी दलील में, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संबंधित उत्तर-पुस्तिकाओं का निरीक्षण विधि की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] ए.आई.आर. 2008 कलकत्ता 118
[2] ए.आई.आर. 2010 दिल्ली 159
[3] ए.आई.आर. 2010 दिल्ली 205
[4] ए.आई.आर. 2010 केरल 151

आवश्यकता को पूरा करता है और निरीक्षण के बाद, प्रत्यर्थीगण पर उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं की आपूर्ति करने के लिए विधि के तहत कोई और बाध्यता नहीं है।

6. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों की विवेचना करने और इस याचिका में शामिल विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की विधिक योजना, इसकी उद्देशिका और वर्तमान मामले के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक विभिन्न प्रावधानों दोनों की जांच करना अत्यंत प्रासंगिक होगा।

7. 2005 के अधिनियम की उद्देशिका यह घोषित करती है कि यह अधिनियम इसलिए पारित किया गया है क्योंकि "लोकतंत्र" के लिए संसूचित नागरिक और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता है जो इसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और सरकारों तथा उनके अभिकरणों को शासितों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए भी आवश्यक हैं। 2005 के अधिनियम की धारा 3, महत्वपूर्ण रूप से, पढ़ती है -

> **"3. सूचना का अधिकार**— इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यद्यपि अधिनियम ने नागरिकों तक सूचना के अधिकारों को सीमित कर दिया है, जैसा कि उपरोक्त प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यह ध्यान देने योग्य है कि सूचना मांगने वाले आवेदक को कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसे ऐसी जानकारी की आवश्यकता क्यों है, सिवाय अपने स्वयं के विवरण से संबंधित कुछ आवश्यक विवरणों के। अधिनियम की धारा 2(च) "सूचना" को परिभाषित करती है। "सूचना" शब्द अपने व्यापक आयाम में, सूचना के लगभग सभी ज्ञात रूपों को समाहित करता है, जो उक्त प्रावधान के सामान्य पठन से स्पष्ट है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

> "2 (च) **"सूचना"** से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी

अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है ;

लोक प्राधिकारी, जो सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है, को 2005 के अधिनियम की धारा 2 (ज) के तहत निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"2(ज) "लोक प्राधिकारी" से कोई ऐसा प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त शासन की संस्था अभिप्रेत है जो—

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित है, और इसके अंतर्गत —

(i) कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन है या उसके द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है;

(ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है;"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान "सूचना का अधिकार" शब्द की परिभाषा है, जिसे 2005 के अधिनियम की धारा 2 (ञ) के तहत परिभाषित किया गया है, जिससे इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य ऐसी सूचना का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है और जिसमें कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना, टिप्पणियां, प्रमाणित प्रतियां आदि लेना शामिल है, जैसा कि इसके खंड **(i)** से **(iv)** में गणना की गई है।

8. 2005 के अधिनियम की धारा 8, जो एक सर्वोपरि प्रभाव रखने वाले खंड के साथ शुरू होती है, स्पष्ट और विस्तृत रूप से अपने विभिन्न खंडों में सूचना के प्रकटन से छूट

प्रदान करती है। खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) में वर्णित 8 मामलों में से, खंड (ङ) और (j) जो वर्तमान मामले के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक हैं और जिनके संबंध में यह कहा गया है कि अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई विशिष्ट जानकारी देने की कोई बाध्यता नहीं होगी, नीचे उद्धृत हैं:

> "8(1)(ङ) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;
>
> (ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है :
>
> परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. 2005 के अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) का खंड (ङ) किसी व्यक्ति को उसके वैश्वासिक संबंध में उपलब्ध जानकारी से संबंधित है। अधिनियम का प्रावधान यह घोषित करता है कि ऐसी प्रकृति की जानकारी देने की कोई बाध्यता नहीं होगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी, जो वैश्वासिक क्षमता में जानकारी रखता है, संतुष्ट न हो कि व्यापक लोक हित ऐसी जानकारी के प्रकटन की मांग करता है।

10. वैश्वासिक संबंध वह है जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष के प्रति विश्वास के रिश्ते में होता है। उक्त संबंध दूसरे पक्ष के हित की रक्षा करने की बाध्यता को जन्म देता है। वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां याचिकाकर्ता किसी अन्य विभागीय उम्मीदवार, जो परीक्षा में उपस्थित हुआ था, के संबंध में परीक्षक द्वारा किए गए मूल्यांकन के बारे में जानकारी के प्रकटन की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता केवल उस जानकारी के प्रकटन की मांग कर रहे हैं जिसमें उनकी अपनी उत्तर-पुस्तिका की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति भी शामिल होगी। यह न तो प्रत्यर्थीगण का मामला है और न ही इस न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री

रखी गई है, चाहे वह विभागीय परीक्षा के मामले में लागू विधि का बल रखने वाले किसी प्रावधान के रूप में हो या परीक्षक और लोक प्राधिकारी के बीच कोई अन्य समझौता हो कि परीक्षक द्वारा किए गए परीक्षा के कार्य को गुप्त और गोपनीय रखा जाएगा और परीक्षकों सहित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संवीक्षा के लिए खुला नहीं होगा। लगभग समान स्थिति में, जहां एक परीक्षार्थी ने विश्वविद्यालय की परीक्षा में अपनी उत्तर-पुस्तिका के निरीक्षण की मांग की थी, 2005 के अधिनियम की धारा 8(1)(ङ) में निहित प्रावधान का सहारा लेकर सूचना के प्रकटन से छूट मांगने वाले वैश्वासिक संबंध की दलील का उत्तर देते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **कलकत्ता विश्वविद्यालय** (पूर्वोक्त) के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "सीबीएसई द्वारा प्रस्तुत वैश्वासिक संबंध की दलील ने हमें प्रभावित नहीं किया है। वैश्वासिक संबंध को एकांतता और गोपनीयता के समान नहीं माना जाना चाहिए। यह वह है जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष के प्रति विश्वास के रिश्ते में होता है और आम तौर पर दूसरे पक्ष के हित की रक्षा करने के लिए बाध्य होता है। एक परीक्षक को उत्तर-पुस्तिका के आकलन/मूल्यांकन का कार्य सौंपते समय परीक्षक और लोक प्राधिकारी के बीच कोई समझौता नहीं होता है कि परीक्षक द्वारा किया गया कार्य लोक प्राधिकारी के सीने से लगा कर रखा जाएगा (अत्यंत गुप्त रखा जाएगा) और किसी के भी द्वारा संवीक्षा/निरीक्षण से मुक्त होगा। कम से कम इस संबंध में हमारे सामने कुछ भी नहीं रखा गया है। चूंकि आरटीआई अधिनियम प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है, भले ही परीक्षक और लोक प्राधिकारी के बीच समझौते में ऐसा कोई खंड हो, वह लोक नीति के विपरीत होगा और इस प्रकार शून्य होगा। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि भले ही लोक प्राधिकारी और परीक्षक के बीच कोई समझौता हो कि बाद वाले द्वारा किया गया आकलन/मूल्यांकन इस आधार पर रोका जाएगा कि यह गोपनीय है और इस संबंध में आश्वासन दिया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गया है, तो भी इसे एक परीक्षार्थी द्वारा अपनी आकलित/मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं तक पहुंच प्राप्त करने के अनुरोध का मुकाबला करने के लिए ढाल के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है और आरटीआई अधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसे आश्वासन पर अभिभावी होगा। 'फिड्यूशियरी' (वैश्वासिक) शब्द के अर्थ की हमारी समझ को ध्यान में रखते हुए, यह मानने की बहुत कम गुंजाइश है कि एक परीक्षक द्वारा उत्तर-पुस्तिकाओं पर की गई नक्काशी/अंकन लोक प्राधिकारी द्वारा विश्वास में रखी जाती है जो आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकटन से मुक्त है। हमें इस तर्क में कोई बल नहीं मिलता है जो तदनुसार खारिज किया जाता है।"

11. **डॉ. श्रीमती एनसन सेबेस्टियन** (पूर्वोक्त) के मामले में, जहां संस्था के साथ काम करने वाले एक वैज्ञानिक ने एक कर्मचारी के खिलाफ घरेलू जांच से संबंधित कुछ दस्तावेजों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए और कई अन्य कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों में प्रविष्टियां प्राप्त करने के लिए सूचना अधिकारी को आवेदन किया, इस तर्क को खारिज करते हुए कि संस्था वैश्वासिक क्षमता में जानकारी रखने के कारण जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि 2005 के अधिनियम की धारा 8(1)(ङ) का कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि यह किसी अन्य के साथ वैश्वासिक संबंध में व्यक्ति के पास उपलब्ध जानकारी से संबंधित है और यह प्रावधान उस रिश्ते पर लागू होता है जो एक मरीज और डॉक्टर, एक वकील और मुवक्किल आदि के बीच मौजूद होता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 8(1)(ङ) में निहित प्रावधान का एक ही नियोक्ता के अन्य सह-कर्मचारियों के बारे में एक कर्मचारी द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

12. वर्तमान मामले में, यह उन्नत तर्क कि 2005 के अधिनियम की धारा 8(1)(ङ) में निहित प्रावधान के अनुसार सूचना के प्रकटन को छूट दी गई है, विधि में स्पष्ट रूप से भ्रामक प्रतीत होता है और अस्वीकार किए जाने योग्य है।

13. जहां तक आवेदन को खारिज करने के अन्य कारण का संबंध है, जिसमें 2005 के अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) में निहित प्रावधान का आह्वान किया गया है, कि मांगी गई

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जानकारी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटन का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से कोई संबंध नहीं है या जिससे व्यक्ति की एकांतता का अनावश्यक अतिक्रमण होगा, यह भी विधि में समान रूप से भ्रामक है और अस्वीकृति का पात्र है। ऐसे मामले में जहां ऐसी व्यक्तिगत जानकारी का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध है, छूट का दावा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने स्वयं उनके द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति की आपूर्ति की मांग की है। दो रिट याचिकाओं में से किसी भी याचिकाकर्ता ने किसी तीसरे पक्ष से संबंधित कोई व्यक्तिगत जानकारी या तो परीक्षक की या परीक्षा आयोजित करने वाले व्यक्ति की या परीक्षा में उपस्थित होने वाले किसी अन्य उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी है। इसके अलावा, इस न्यायालय को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान मामले में सरकारी विभाग में निचले पद से उच्च पद पर पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए विभागीय एजेंसी द्वारा परीक्षा का संचालन निजी गतिविधियां नहीं हैं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। इसलिए, जहां एक उम्मीदवार ने विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में अपने स्वयं के प्रदर्शन के बारे में जानकारी मांगी और उस संबंध में अपनी स्वयं की उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रति की मांग की, जो परीक्षक द्वारा आकलित/मूल्यांकित की गई हैं, बिना परीक्षा की प्रक्रिया और संचालन से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत जानकारी मांगे, वहां 2005 के अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के प्रावधान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि सूचना के उक्त प्रकटन से किसी व्यक्ति की एकांतता का अनावश्यक अतिक्रमण होगा। प्रत्यर्थीगण के अभिवचन में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं रखे गए हैं और न ही मामले के अभिलेखों से उत्पन्न हुए हैं। एक परीक्षक द्वारा उत्तर-पुस्तिका की जांच और मूल्यांकन और प्रदर्शन के आकलन पर उसके द्वारा दिए गए अंकों का परीक्षक या परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार लोगों की गोपनीयता से कोई लेना-देना नहीं है। **डॉ. श्रीमती एनसन सेबेस्टियन** (पूर्वोक्त) के मामले में, जहां एक कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी के खिलाफ घरेलू जांच से संबंधित दस्तावेजों से संबंधित जानकारी मांगी और अपीलकर्ता के छह अन्य कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट में प्रविष्टियां भी मांगी, 2005 के अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के तहत छूट के दावे को खारिज करते हुए, केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 8(1)(ञ) के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियोक्ता द्वारा प्रबंधित कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट को किसी कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित अभिलेख नहीं माना जा सकता है, जिसका प्रकटन अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के तहत छूट प्राप्त कहा जा सकता है। विचाराधीन दो याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का मामला बहुत बेहतर स्थिति में है। इसलिए, मेरी सुविचारित राय है कि अपनी आकलित/मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिका की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज करना अवैध है क्योंकि 2005 के अधिनियम की धारा 8(1)(ङ) और धारा 8(1)(ञ) के तहत किसी भी छूट का दावा नहीं किया जा सकता है।

14. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील कि चूंकि याचिकाकर्ताओं को अपनी उत्तर-पुस्तिका के निरीक्षण की अनुमति दी गई है, इसलिए उत्तर-पुस्तिका की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने की कोई और बाध्यता नहीं है, 2005 के अधिनियम की धारा 3 में निहित प्रावधान और अधिनियम की धारा 2(ञ) के तहत "सूचना का अधिकार" शब्दों की परिभाषा को देखते हुए खारिज किए जाने योग्य है। 2005 के अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट रूप से बताती है कि अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "सूचना का अधिकार" का क्या अर्थ है, यह खंड (ञ) के तहत इसकी परिभाषा से बिल्कुल स्पष्ट है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"2(ञ) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का अधिकार अभिप्रेत है, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है—

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(iv) डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से

सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है;अभिप्राप्त करना"

15. इसलिए, सूचना के अधिकार में दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां लेने का अधिकार शामिल होगा और केवल निरीक्षण प्रत्यर्थीगण को उनकी बाध्यता से मुक्त नहीं करता है और न ही यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को पूरी जानकारी दी गई है। वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां याचिकाकर्ता अपनी उत्तर-पुस्तिका के निरीक्षण के बाद संतुष्ट महसूस करते हों। याचिकाकर्ताओं का आवेदन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्होंने संबंधित विषयों में अपनी उत्तर-पुस्तिका की प्रमाणित प्रतियों की मांग की थी। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के सूचना के अधिकार में उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां लेने का अधिकार भी शामिल है, जिससे प्रत्यर्थीगण द्वारा इनकार नहीं किया जा सकता है।

16. उत्तर-पुस्तिकाओं में उत्तर के संबंध में सूचना की आपूर्ति से संबंधित समान मुद्दा, **प्रीतम रूज** (पूर्वोक्त) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, जिसमें एक परीक्षार्थी ने प्रार्थना की थी कि उसे अपने उत्तर पत्रों के निरीक्षण की अनुमति दी जाए। याचिका स्वीकार कर ली गई थी। आदेश को खंडपीठ के समक्ष अपील में चुनौती दिए जाने पर, खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई (ए.आई.आर. 2009 कलकत्ता 97)। वर्तमान मामले के तथ्य समान हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. फलस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित याचिकाकर्ताओं को उनकी मूल्यांकित/आकलित उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां, आवश्यक शुल्क के भुगतान पर, यदि पहले से भुगतान नहीं किया गया है, तो आपूर्ति करें। इस आदेश की एक प्रति संबंधित मामले (रिट याचिका (सी) संख्या 5857 वर्ष 2009) में भी अभिलेख पर रखी जाए।

सही/-
मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Bhumesh Bharti

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur